



## The Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958

Act 15 of 1958

Keyword(s):

Central Act Amendment, Court Fees Act, Court, Fee

Amendments appended: 13 of 2011, 3 of 2013

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

**MADHYA PRADESH ACT**

No. 15 of 1958

**THE COURT FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958****TABLE OF CONTENTS**

Sections	Page
1. Short title.	29
2. Amendment of Schedules to the Court Fees Act, 1870 (No. VII of 1870);	29
3. Continuance of stamps of old denominations.	29

---

## MADHYA PRADESH ACT

(No. 15 of 1958)<sup>1</sup>

### THE COURT FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958

(Received the assent of the Governor on the 23rd June 1958; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary on the 3rd July, 1958.)

*An Act to amend the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.*

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958.

**Short title.**

2. In the Court Fees Act, 1870—

(i) in Schedules I and II for the words "Two annas" "Five annas" "Five annas and four pies" or "Five annas and pies four", "Eight annas", "Ten annas" and "Ten annas and eight pies", wherever they occur whether in conjunction with any other words or otherwise, the words "Ten Naye Paise", "Thirty Naye Paise", "Thirty-five Naye Paise", "Fifty Naye Paise", "Sixty Naye Paise" and "Sixty-five Naye Paise" shall be substituted respectively;

**Amendment of Schedules to the Court Fees Act, 1870 (No.VII of 1870).**

(ii) in Schedule I in the Table of rates of *advolorem* fees leviable on the institution of suits under Article I-A, in column (3)—

(a) for the letters "a. p.", the letters "N.P." shall be substituted; and

(b) for the figures "8-0", "5-0" and "10-0", the figures "50", "30" and "60" shall be substituted respectively; and

(iii) in Schedule III for the letters "a-p." with separate columns the letters "N. P." with a single column shall be substituted.

3. The stamps denoting the fees chargeable under this Act in old denominations shall continue to be valid for a period of six months from the date of the commencement of the Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958 (15 of 1958) to the same extent to which they would have been valid if the said Act had not been passed.

**Continuance of stamps of old denominations.**

1. For Statement of Objects and Reasons (in English) see "Madhya Pradesh Gazette," Extraordinary dated the 15th April 1958, page 667 and (in Hindi) 668. For proceedings in Assembly see Madhya Pradesh Vidhan Sabha Proceedings, 1958, Volume III, pages 2924 to 2927.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 2602-164-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०११

### न्यायालय फीस ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २६ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ में, खण्ड (ख) में, मद (एक), (दो) तथा (तीन) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(एक) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये तक हो.

न्यूनतम दो सौ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए अनादृत चैक की रकम का पांच प्रतिशत.

(दो) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख तक हो.

न्यूनतम पांच हजार रुपये और ऐसी रकम पर जो एक लाख रुपये से अधिक हो, चार प्रतिशत.

(तीन) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम पांच लाख रुपये से अधिक हो.

न्यूनतम इक्कीस हजार रुपये और ऐसी रकम पर, जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए तीन प्रतिशत.”

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2011

क्र. 2603-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.13 of 2011.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT)  
ADHINIYAM, 2011.

[ Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011: assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 26th April,2011.]

**An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

**Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. The court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

**Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

3. In the Schedule II to the principal Act, in article 1, in clause (b), for items (i), (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following items and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

**Amendment of Schedule II.**

- |  |  |
|--|--|
| " (i) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is upto one lakh                                       | Five percent of the amount of dishonoured cheque subject to the minimum of two hundred rupees.   |
| (ii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than one lakh rupees but upto five lakh rupees. | Minimum five thousand rupees, plus four percent on the amount in excess of one lakh rupees.  |
| (iii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than five lakh rupees.                         | Minimum twenty one thousand rupees, plus three percent on the amount in excess of five lakh rupees subject to maximum one lakh fifty thousand rupees." |

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 145-10-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१३.

## न्यायालय फीस ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०१२.

[ दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० ( १८७० का सं. ७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 2 का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद ११ में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, उचित फीस से संबंधित कालम में, शब्द "अपील में दावाकृत वर्धित रकम का दस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए अपील में दावाकृत वर्धित रकम का ढाई प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 146-10-इक्कीस-अ (प्रा)/अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 3 सन् 2013 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2013.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

**An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012.

Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II to the principal Act, in article 11, in clause (a), in sub-clause (i), in the column pertaining to proper fee, for the words "Ten percent of the enhanced amount claimed in appeal", the words "Two and one half percent of the enhanced amount claimed in appeal subject to a maximum of one lac rupees" shall be substituted.